झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 4742/2022

लक्ष्मी गोपे उर्फ लक्ष्मी गोपे, पत्नी स्व. हरजिंदर सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी- मकान सं. 632, ज़ोन सं. 4, बिरसानगर, डाकघर- एवं थाना- बिरसानगर, ज़िला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. बलजीत कौर, पत्नी स्व. राजेंद्र सिंह, निवासी- मकान सं. डी/23, खुटाडीह, डाकघर- एवं थाना- सोनारी, ज़िला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री जितेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री शिव शंकर कुमार, अतिरिक्त लोक अभियोजक

प्रतिवादी सं. 2 की ओर से : श्री मोहम्मद असगर, अधिवक्ता

श्री अमित मिश्रा, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर किया गया है, जिसमें 10.06.2022 को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर द्वारा बिरसानगर थाना कांड संख्या 84/2021, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 406, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया है, के संदर्भ में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। इसके साथ ही, 09.06.2022 को दाखिल आरोप पत्र और 01.09.2022 को आरोप तय करने के आदेश सहित याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरे आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को संपत्ति का मालिक बताकर शिकायतकर्ता के पति से संपत्ति बेचने के लिए एक समझौता किया। विचारणीय राशि ₹2,50,000/- निर्धारित की गई थी। शिकायतकर्ता के पति ने 07.03.2005 को चेक के माध्यम से ₹40,000/- का अग्रिम भुगतान किया और बाद में 07.06.2005 को एक अन्य चेक द्वारा ₹1,00,000/- का भुगतान भी किया। 07.06.2005 को आरोपी ने संपत्ति के वास्तविक भौतिक कब्जे को शिकायतकर्ता के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए भी सौंप दिया। शिकायत के पैराग्राफ-3 में एक विरोधाभासी बयान दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने यह आश्वासन दिया कि शेष ₹1,10,000/- के भुगतान पर पूरी जमीन को खरीदार के कब्जे में दे दिया जाएगा। शिकायतकर्ता के पति ने पूरी जमीन को पक्का दीवार से घेर लिया। 01.08.2005 को, शिकायतकर्ता के पति ने एक अन्य बिक्री समझौते में ₹50,000/- का भुगतान किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता के पति के पक्ष में पूरी संपत्ति को तुरंत शेष ₹60,000/- का भुगतान करने पर हस्तांतरित करने का वादा किया। शिकायतकर्ता का पति याचिकाकर्ता से शेष ₹60,000/- के भुगतान के लिए मिलने गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के पति को गालियाँ दीं। 20.11.2005 को शिकायतकर्ता के पति का निधन हो गया। मई माह में, जब COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, शिकायतकर्ता ने देखा कि कुछ अन्य व्यक्ति उक्त संपत्ति पर नई निर्माण गतिविधि कर रहे थे और दीवार को गिरा रहे थे। शिकायतकर्ता ने जोरदार आपत्ति जताई, लेकिन निर्माण करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने पूरी जमीन आरोपी से खरीदी है और इस तरह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि शिकायतकर्ता ने कथित भुगतान की गई राशि का पूरा मूल्य 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं चुकाया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस को भेजा गया है, जबकि यह कानून के अनिवार्य प्रावधान के अनुसार शपथपत्र द्वारा समर्थित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पक्षकारों के बीच विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और सिविल मुकदमा दायर करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए, केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए यह झूठा मामला कथित कारण के 16-17 साल बाद दर्ज किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लेन-देन की शुरुआत से शिकायतकर्ता को धोखा देने की कोई मंशा नहीं थी, न ही सौंपे गए संपत्ति के धोखाधड़ी से गबन की कोई शिकायत की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [(2019) 9 एससीसी 148]** मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है, जिसके पैराग्राफ-14 में कहा गया है:

> *"इसके अलावा, इस न्यायालय ने कई मामलों में सिविल विवादों, जैसे कि अनुबंधात्मक दायित्वों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह दी है (जैसा कि *गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य* [गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (सिविल) 1188 : (2013) 1 एससीसी (क्रि) 160 : (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] में संदर्भित किया गया है)। <u>विधायिका ने केवल उन्हीं उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में रखने का इरादा किया है, जो धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रामक उत्प्रेरण के साथ किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनैच्छिक और अक्षम हस्तांतरण होते हैं, जो धारा 415 आईपीसी के तहत आते हैं।"</u>*

और उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि वे उल्लंघन जो धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रामक उत्प्रेरण के साथ होते हैं और जिनके परिणामस्वरूप अनैच्छिक और अक्षम हस्तांतरण होते हैं, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध होते हैं।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के **दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जो **(2023) 3 एससीसी 423** में प्रकाशित है, जिसमें पैराग्राफ-31 में कहा गया है:

"31. समन आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब शिकायतकर्ता अपराध का खुलासा करे, और जब ऐसा सामग्री हो जो अपराध के आवश्यक तत्वों का समर्थन और निर्माण करती हो। इसे हल्के में या सामान्य रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। जब कानून के उल्लंघन का आरोप स्पष्ट रूप से विवादास्पद और संदिग्ध हो, या तो तथ्य की कमी और अस्पष्टता के कारण, या तथ्य पर कानून के अनुप्रयोग के कारण, मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने का ध्यान रखना चाहिए। कानून प्रावधानों की प्रशंसा के बिना समन जारी करना और उन्हें तथ्यों पर लागू करना एक निर्दोष व्यक्ति को अभियोजन/मुकदमा खड़ा करने के लिए बुलाए जाने का परिणाम हो सकता है। अभियोजन की शुरुआत और अभियुक्त को मुकदमे के लिए बुलाए जाने के कारण, मौद्रिक नुकसान के अलावा, रक्षा की तैयारी के लिए समय और प्रयास का बलिदान, समाज में अपमान और बदनामी का कारण बनता है। यह अनिश्चित समय की चिंता का कारण बनता है।"

और यह तर्क दिया कि समन आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब शिकायतकर्ता अपराध का खुलासा करे और जब ऐसा सामग्री हो जो अपराध के आवश्यक तत्वों का समर्थन करती हो और इसे हल्के में या सामान्य रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

6. अतः, यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 10.06.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा बिरसानगर पी.एस. केस नंबर 84/2021 के संबंध में पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो जी.आर. संख्या 874/2022 के अनुरूप है, और दिनांक 09.06.2022 की चार्जशीट और दिनांक 01.09.2022 का आरोप तय करने का आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक प्रक्रिया शामिल है, जो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, को निरस्त किया जाए।

7. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक और प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने संज्ञान लेने का आदेश दिनांक 10.06.2022, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा बिरसानगर पी.एस. केस संख्या 84/2021 के संबंध में पारित किया गया है, और जी.आर. संख्या 874/2022 के अनुरूप चार्जशीट दिनांक 09.06.2022 और आरोप तय करने का आदेश दिनांक 01.09.2022 को निरस्त करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

8. बार में किए गए विरोधाभासी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को सावधानीपूर्वक जांचने के बाद, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** मामले में, जो **(2015) 6 एससीसी 287** में प्रकाशित है, दी गई राय के अनुसार, जो पैराग्राफ-30 और 31 में कहा गया है:

"30. हमारे विचार में, इस देश में एक ऐसा चरण आ गया है जहां धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन को शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो उस व्यक्ति द्वारा समर्थित हो जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने की याचना करता है। इसके अलावा, एक उपयुक्त मामले में, माननीय मजिस्ट्रेट सत्यापन कर सकते हैं और आरोपों की सच्चाई की भी जांच कर सकते हैं। यह शपथ पत्र याचिकाकर्ता को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। हमें ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार के आवेदन सामान्य रूप से बिना किसी जिम्मेदारी के दायर किए जाते हैं ताकि कुछ व्यक्तियों को परेशान किया जा सके। इसके अलावा, यह अधिक चिंताजनक और खतरनाक हो जाता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को उठाने की कोशिश करता है जो एक सांविधिक प्रावधान के तहत आदेश पारित कर रहा है जिसे उस अधिनियम के ढांचे के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। लेकिन यह आपराधिक अदालत में अनुचित लाभ लेने के लिए नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोई व्यक्ति स्कोर निपटाने के लिए दृढ़ संकल्प कर रहा हो।

31. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धारा 156(3) के तहत याचिका दायर करते समय धारा 154(1) और 154(3) के तहत पूर्व आवेदन होने चाहिए। दोनों पहलुओं को स्पष्ट रूप से याचिका में व्यक्त किया जाना चाहिए और इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 156(3) के तहत आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित हो, यह निर्देश देने का उद्देश्य है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति सतर्क हो और यह भी प्रयास करे कि कोई गलत शपथ पत्र न बनाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार शपथ पत्र झूठा पाया गया तो वह कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। इससे उसे मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए हल्के में आवेदन करने से रोकने का प्रयास होगा। इसके अलावा, हम पहले ही कह चुके हैं कि मामले की आरोपों की प्रकृति को देखते हुए माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सत्यता की भी जांच की जा सकती है। हमें ऐसा कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि कई मामले जो वित्तीय क्षेत्र, वैवाहिक विवाद/परिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले और जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी/लाचेस होते हैं, वे ललिता कुमारी [(2014) 2 एससीसी 1 : (2014) 1 एससीसी (क्रि) 524] में उल्लिखित हैं। इसके अलावा, माननीय मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।" (जोर दिया गया)

यह कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन को शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने की याचना करता है ताकि आवेदन करने वाला व्यक्ति सतर्क हो और यह भी प्रयास करे कि कोई गलत शपथ पत्र न बनाए।

9. यह भी एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य** मामले में, जो **(2023) 5 एससीसी 360** में प्रकाशित है, कहा गया है, जिसके पैराग्राफ-13 में कहा गया है:

> *"13. अनुबंध का उल्लंघन तब तक धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन का कारण नहीं बनता जब तक कि धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा लेन-देन की शुरुआत में ही न दिखाया जाए। केवल वादे को निभाने में विफलता के आरोप पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 2 ने अपना मामला तब से सुधारा है जब पहली शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं था, बल्कि केवल संपत्ति दलालों के खिलाफ था, जो कि बाद की शिकायतों में अपीलकर्ता का नाम जोड़ा गया था। पहली शिकायत पर, केवल भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की गई थी। जब पहले शिकायत के आधार पर अपराध साबित हुआ, दूसरी शिकायत सुधारे गए संस्करण के साथ दर्ज की गई, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए, जो पहले की शिकायत में नहीं थे। पूरे विचार को एक दीवानी विवाद को आपराधिक में बदलने और अपीलकर्ता पर कथित रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए दबाव डालने का लगता है। आपराधिक अदालतों का उपयोग स्कोर निपटाने या दीवानी विवादों को सुलझाने के लिए दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जहां कहीं भी आपराधिक अपराधों के तत्व बने होते हैं, आपराधिक अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। जिस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, वह बिक्री विलेख पंजीकरण की अंतिम तारीख के लगभग तीन साल बाद दर्ज की गई थी। कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" (जोर दिया गया)*

अनुबंध के उल्लंघन से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में ही धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया गया हो।

10. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है कि उसने शिकायतकर्ता के पति को धोखा देने का इरादा किया था, जिससे उसने कथित रूप से अग्रिम लिया था, हालांकि इस संबंध में कोई दस्तावेज़

शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अब तक रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, जबकि इस आपराधिक विविध याचिका की लंबितता के दौरान शिकायतकर्ता को इसके लिए अवसर भी दिया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप भी नहीं है कि उसने सौंपे गए संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है कि उसने कोई जालसाजी की है या किसी भी झूठे दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया है। शिकायत में संपत्ति के कब्जे को याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के पति को सौंपे जाने के संबंध में विरोधाभासी बयान दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता अपने मामले को लेकर बहुत निश्चित नहीं है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोपों और मामले की जांच के दौरान एकत्रित की गई सामग्रियों, जिसमें गवाहों के बयान भी शामिल हैं, जो कि धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं, को उनकी संपूर्णता में सत्य मानने के बाद भी, याचिकाकर्ता के खिलाफ जिन अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, उनमें से कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है और यह एक उपयुक्त मामला है जहां याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 10.06.2022 को बिरसानगर पी.एस. केस नंबर 84/2021 के संबंध में पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो जी.आर. संख्या 874/2022 के अनुरूप है, और चार्जशीट दिनांक 09.06.2022 तथा आरोप तय करने का आदेश दिनांक 01.09.2022, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक प्रक्रिया शामिल है, जो अब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है, याचिकाकर्ता की प्रार्थना के अनुसार, को रद्द और निरस्त किया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत होती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 28 फरवरी 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**